नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर
स्थापित २००५ ई.
7897475917, 9794299451
Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक..... दिनांक : 22-09-2020

प्रकाशनार्थ

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं ग्रामीण भारत का भविष्य विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम)

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर में उन्नत भारत अभियान के तत्वावधान में व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता **डॉ. राजशरण शाही, सदस्य संचालन समिति, नई शिक्षा नीति, उत्तर प्रदेश** ने ''**नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं ग्रामीण भारत के भविष्य**'' विषय पर बोलते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति लैब से लैण्ड तक की यात्रा से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेंगी। पूर्वकालीन शिक्षा नीति के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि अंगेजों ने अपना शासन लम्बे समय तक चलाने के लिए, भारतीय शिक्षा से भारतीय मूलभावनाओं को काटने के लिए भारत की मातृभाषा को शिक्षा से काटा तथा भारतीयो को मातृभाषा से काटकर उन्हें उनके मूल्यों एवं परम्पराओं से काटने का कार्य किया। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें हमारे देश के गाँवों, संस्कारों, मूलभावनाओं एवं मातृभाषा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगी। शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की क्रिया। भारत की बड़ी जनसंख्या गॉवों में बसती है, अब तक बालकों की मातृभाषा, जीवन की भाषा एवं अध्ययन की भाषा अलग–अलग थी जिसे नई शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़कर एक करने का प्रयास किया गया है। बालक अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में सरलता एवं शीघ्रता से सीखता है। अब कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है तथा किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है अर्थात् अब बालक जो भाषा अपने माता–पिता, आस–पड़ोस में सुनेगा उसी भाषा में शिक्षा भी प्राप्त करेगा जिससे उसके बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। बालको के मस्तिष्क का विकास 3–8 वर्ष की आयु तक 85 प्रतिशत हो जाता है ऐसे में जब बालक 6 वर्ष की आयु में विद्यालय जाता था तो तीन से छः वर्ष की आयु का समय विद्या एवं अच्छे स्वास्थ्य से वंछित रह जाता था, नई शिक्षा नीति बच्चे के न केवल मस्तिष्क वरन् समग्र विकास में सहायक होगी।

उन्होने आगे कहा कि इस शिक्षा नीति में ग्रामीण भारत की कला, संस्कृति और रोजगार के शिक्षालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से ग्रामीण भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधार कला और विज्ञान, व्यवासायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच का अन्तर समाप्त कर शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति ज्ञान के साथ–साथ कौशल का विकास कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाएगी। ग्रामीण भारत के लोकजीवन में पलने वाली लोक कलाओ, संस्कृति एवं रोजगार को शिक्षालयों के माध्यम से समाज तक ले जाने का कार्य यह शिक्षा नीति करेगी। अब तक लोहार, कुम्हार, बढ़ई गॉव तक रह जाते थे परन्तु नई शिक्षा नीति से इन विद्याओं का अध्ययन के साथ विकास का माध्यम बनेगी। ग्रामीण भारत के उत्थान के अभियान के रूप में यह शिक्षा नीति आयी है। राधाकृष्णन कमीशन ने पहली बार ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना की थी कि भारत के विश्वविद्यालयों को ग्रामीण समग्र विकास के सशक्त साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति इसी कल्पना को साकार करेगी। नई शिक्षा नीति हमें हमारी संस्कृति एवं परिवेश से जोड़ेगी। इस शिक्षा नीति में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए ऑगनबाड़ी केन्द्रो स्कूल परिसरों के कार्यक्रमों में माता–पिता और शिक्षकों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। गॉवों के स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थापना कर पढ़ने की संस्कृति का विस्तार किया जाएगा साथ ही इससे समुदाय को भी लाभ मिलेगा। नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करेगी क्योकि इसका मूल तत्व है अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान एवं अपनी दक्षता को समझकर उन पर आत्मविश्वास विकसित करना। यह आत्मविश्वास अपनी भाषा से सतत जुड़ाव से मिलता है। जो भी व्यक्ति अपने लोक उद्यमों को जानेगा, बुझेगा उनकी खूबियॉ विश्व में फैला सकता है। लोकदक्षता एवं स्थानीय उत्पादों को महत्व देकर '**वोकल फॉर लोकल**' का काम यह शिक्षा नीति कर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में का सतत प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आरती सिंह एवं आभार ज्ञापन डॉ. ब्रजभूषण लाल ने किया।

(कविता मध्यान)
प्रभारी, उन्नत भारत अभियान